



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 171]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 2, 2016/ज्येष्ठ 12, 1938

No. 171]

NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 2, 2016/JYAISTHA 12, 1938

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय)

जांच शुरूआत संबंधी अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जून, 2016

विषय : चीन जन गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित 'अलाय या गैर-अलाय इस्पात के वायर राड' के आयातों से संबंधित पाटनरोधी जाँच की शुरूआत— के संबंध में ।

सं. 14/17 /2016-डीजीएडी.— मै. स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि, मै. राष्ट्रीय इस्पात निगम लि., मै. ऊषा मार्टिन लिमिटेड और मै. जेएसडब्लू स्टील लि. (जिन्हें आगे याचिकाकर्ता कंपनियां या आवेदक भी कहा गया है) ने समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और समय-समय पर यथासंशोधित सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उन पर पाटनरोधी शुल्क का आकलन और संग्रहण तथा क्षतिनिर्धारण) नियमावली, 1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) के अनुसार निर्दिष्ट प्राधिकारी के समक्ष एक याचिका दायर की है जिसमें चीन जन. गण., (जिसे आगे संबद्ध देश भी कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "अलाय या गैर-अलाय इस्पात के वायर राड" (जिसे आगे संबद्ध वस्तु या विचाराधीन उत्पाद भी कहा गया है) के कथित पाटित आयातों पर पाटनरोधी जाँच की शुरूआत और उन पर पाटनरोधी शुल्क लगाने का अनुरोध किया गया है।

2. और यत: प्राधिकारी प्रथम दृष्टया यह पाते हैं कि संबद्ध देशों के मूल की अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटन, कथित पाटन और क्षति के बीच कारणात्मक संबंध के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हैं जो पाटनरोधी जाँच की शुरूआत का उचित ठहराते हैं, इसलिए प्राधिकारी एतद्वारा उक्त नियमावली के अनुसार कथित पाटन और घरेलू उद्योग को हुई परिणामी क्षति की जाँच की शुरूआत करते हैं ताकि कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव

का निर्धारण किया जा सके और पाटनरोधी शुल्क की उस राशि की सिफारिश की जा सके जिसे यदि लगाया जाए तो वह घरेलू उद्योग को हुई 'क्षति' को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगी।

विचाराधीन उत्पाद

3. विचाराधीन उत्पाद लोहे या गैर-अलाय इस्पात या अलाय इस्पात की छड़े और राड, अनियमित वाउंड काइलों में हाट-रोल्ड हैं (जिन्हें आम तौर पर 'वायर राड' के रूप में जाना जाता है)। ये उत्पाद प्राइम या गैर-प्राइम श्रेणी के और सभी आकारों में होते हैं। ये उत्पाद इस्पात की विभिन्न गुणवत्ताओं के अनुपालन में होते हैं जिनमें इलेक्ट्रोड, प्री कटिंग, फोर्जिंग, कोल्ड हेडिंग, कम/मध्यम/उच्च कार्बन इस्पात, ड्राइंग, बाल बियरिंग इस्पात, केस हार्डेनिंग इस्पात, स्प्रिंग इस्पात, जंगरोधी इस्पात, वैदरिंग इस्पात, संरचनात्मक इस्पात और इस्पात की अनेक अन्य गुणवत्ताएं शामिल हैं परंतु इन तक सीमित नहीं हैं। तथापि निम्नलिखित उत्पाद विचाराधीन उत्पाद के दायरे में शामिल नहीं हैं।

क) बार और राड जिनमें रोलिंग प्रक्रिया के दौरान उत्पादित इंडेन्टेशंस, रिब्स, गूब्स या अन्य विकृतियां होती हैं तथा जो 72131090 टैरिफ मद के अंतर्गत आते हैं (आम तौर पर रिबार्स या टीएमटी बारों के रूप में जाना जाता है)

ख) टैरिफ शीर्ष 7221 के अंतर्गत आने वाले स्टेनलैस स्टील के बार और राड

ग) टैरिफ मद 72271000 के अधीन आने वाले उच्च गति इस्पात के बार और राड

4. पीयूसी का प्रयोग अनेक अनुप्रयोगों और क्षेत्रों जैसे आटोमोटिव कलपुर्जे, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स, नट और बोल्ट सहित फास्टनर्स, कीलें, रेल के स्लीपर्स, सामान्य इंजीनियरिंग, भवन निर्माण उद्योग के लिए बाइंडिंग वायर, आर्मर्ड केबल आदि में किया जाता है।

5. पीयूसी को सीमाशुल्क टैरिफ शीर्ष 7213 और 7227 के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। तथापि सीमाशुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक हैं और वर्तमान जाँच के दायरे पर किसी भी प्रकार से बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

6. आवेदक ने दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित की जा रही संबद्ध वस्तु और भारत में पाटित की जा रही संबद्ध वस्तु समान वस्तुएं हैं। आवेदकों ने दावा किया है कि आवेदकों द्वारा उत्पादित की जा रही और संद्ध देश के मूल की अथवा वहां से आयात किया जा रहा विचाराधीन उत्पाद भौतिक और रासायनिक विशेषताओं, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, उत्पाद विनिर्देशन, कीमत निर्धारण, वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण जैसी अनिवार्य उत्पाद विशेषताओं की दृष्टि से तुलनीय हैं। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं और इसलिए नियमों के अंतर्गत इन्हें समान वस्तु माना जाना चाहिए। अतः वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ भारत में आवेदकों द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु को संबद्ध देश के मूल की अथवा वहां से आयातित की जा रही संबद्ध वस्तु के 'समान वस्तु' माना जा रहा है।

घरेलू उद्योग

7. यह आवेदन मै. स्टील अथारिटी आफ इंडिया लि, मै. राष्ट्रीय इस्पात निगम लि., मै. ऊषा मार्टिन लिमिटेड और मै. जेएसडब्लू स्टील लि. द्वारा दायर किया गया है। रिकार्ड में उपलब्ध सूचना के अनुसार पूर्वोक्त तीन उत्पादकों के उत्पादन का भारतीय उत्पादन में कुल घरेलू उत्पादन का प्रमुख हिस्सा बनता है। इसके अलावा यह आवेदन दो घरेलू उत्पादकों अर्थात टाटा स्टील लिमिटेड और जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड द्वारा समर्थित है।

8. इस प्रकार, आवेदन पूर्वोक्त तीन घरेलू उत्पादकों की योग्यता के संबंध में नियमावली के नियम 2(ख) और नियम 5(3) की अपेक्षाओं को पूरा करता है और यह कि उन्हें संबंधित नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग (डीआई) माना जाता है।

शामिल देश

9. वर्तमान जाँच में शामिल देश चीन जन. गण. है।

सामान्य मूल्य

चीन जन. गण.

10. चीन जन. गण. के संबंध में, आवेदकों ने बताया है कि चीन जन. गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 और 8 के अनुसार किया जाना चाहिए। नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 8 के अनुसार, यह माना गया है कि चीन जन. गण. में संबद्ध वस्तु के उत्पादक गैर बाजार अर्थव्यवस्था के अधीन प्रचालनरत हैं। उक्त गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की मान्यता और प्रतिवादी निर्यातकों द्वारा उसके खंडन के अधीन चीन जन. गण. के लिए संबद्ध वस्तु के सामान्य मूल्य का अनुमान नियमावली के अनुबंध 1 के पैरा 7 के अनुसार किया गया है। आवेदकों ने बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक व्ययों और तर्कसंगत लाभ को शामिल करने के लिए विधिवत रूप में समायोजित भारत में उत्पादन लागत के आधार पर चीन जन. गण के लिए सामान्य मूल्य की गणना की है। आवेदकों के सामान्य मूल्य संबंधी दावों पर जाँच शुरूआत के प्रयोजनार्थ विचार किया गया है।

निर्यात कीमत

11. आवेदक ने भारत में आईबीआईएस से उपलब्ध सौदावार आयात आकड़ों के आधारपर संबद्ध देश के लिए निर्यात कीमत निर्धारित की है। संबद्ध देश के लिए अंतर्देशीय भाड़े, समुद्री भाड़े, समुद्री बीमा, सीमाशुल्क प्रहस्तन और निकासी प्रभारों और वैट के गैर-वापसी योग्य हिस्से के संबंध में कीमत समायोजन किए गए हैं।

पाटन मार्जिन

12. सामान्य मूल्य की तुलना कारखाना द्वार पर निर्यात कीमत के साथ की गई है जो संबद्ध देशों के संबंध में पर्याप्त पाटन मार्जिन दर्शाती है। इस बात के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य हैं कि संबद्ध देशों से संबद्ध वस्तु का सामान्य मूल्य कारखाना-द्वार निर्यात कीमत से काफी अधिक है जिससे प्रथम दृष्टया पता चलता है कि संबद्ध देश से निर्यातकों द्वारा भारतीय बाजार में संबद्ध वस्तु का पाटन किया जा रहा है।

13. भारी पाटन मार्जिन के पर्याप्त प्रथम-दृष्टया साक्ष्य हैं जो पाटनरोधी जाँच की शुरूआत को उचित ठहराते हैं।

क्षति और कारणात्मक संबंध

14. आवेदकों ने दावा किया है कि संबद्ध देश से कथित पाटन के परिणामस्वरूप उन्हें वास्तविक क्षति हुई है और उन्होंने क्षति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं जो आयातों में समग्र रूप से और घरेलू उत्पादन और घरेलू मांग के संबंध में वृद्धि के रूप में हुई है। संबद्ध देशों से पाटन के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग की क्षमता उपयोग, बाजार हिस्से, मालसूची, लाभ, नियोजित पूंजी पर आय, नकद लाभ आदि में गिरावट आई है।

15. आवेदकों ने प्रतिकूल कीमत प्रभावों का भी दावा किया है जो कीमत ह्रास, कम कीमत पर बिक्री और कीमत कटौती/कीमत न्यूतीकरण से साक्ष्यांकित होता है। प्राधिकारी मानते हैं कि संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तु के पाटित आयातों के कारण आवेदकों को क्षति होने के पर्याप्त प्रथम दृष्टया साक्ष्य मौजूद हैं जो पाटनरोधी जाँच की शुरूआत को न्यायोचित ठहराते हैं।

जाँच अवधि

16. वर्तमान जाँच के प्रयोजनार्थ जाँच अवधि (पीओआई) जुलाई, 2015 से दिसम्बर, 2015 तक की है। तथापि, क्षति जाँच अवधि में अप्रैल 2012 से मार्च 2013, अप्रैल 2013 से मार्च 2014, अप्रैल 2014 से मार्च 2015, अप्रैल 2015 से दिसंबर 2015 (वार्षिकीकृत) और जाँच की अवधि (पीओआई) शामिल होगी।

पूर्व प्रभाव से शुल्क लगाना

17. आवेदकों ने निम्नलिखित कारणों की वजह से पूर्व प्रभाव से पाटनरोधी शुल्क लगाने के लिए अनुरोध किया है:

- क. पाटन का इतिहास है और आयातकों को इस बात से अवगत होना चाहिए कि क्षति होती है।
- ख. घरेलू उद्योग को क्षति तुलनात्मक कम समय में संबद्ध वस्तुओं के बड़े पैमाने पर पाटन के कारण हुई है।

जिनके समय पाटित आयातित संबद्ध वस्तुओं की मात्रा तथा अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लगाए जाने वाले पाटनरोधी शुल्क के उपचारात्मक प्रभाव का गंभीरतापूर्वक क्षीण होने की संभावना है।

18. हितबद्ध पक्षकार इस संबंध में अपने अनुरोध कर सकते हैं।

सूचना प्रस्तुत करना

19. संबद्ध देश में ज्ञात निर्यातकों, भारत में स्थित उनके दूतावास के जरिए उनकी सरकार, संबद्ध वस्तु से संबंधित समझे जाने वाले भारत में ज्ञात आयातकों व प्रयोक्ताओं और घरेलू उद्योग को अलग-अलग सूचित किया जा रहा है ताकि वे नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से समस्त संगत सूचना प्रस्तुत कर सकें। कोई अन्य हितबद्ध पक्षकार भी नीचे निर्धारित की गई समय सीमा के भीतर विहित प्रपत्र में एवं ढंग से जाँच से संगत अनुरोध कर सकता है। सूचना/अनुरोध निम्नलिखित को प्रस्तुत किए जाएः

निर्दिष्ट प्राधिकारी

पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

भारत सरकार

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5 संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

समय-सीमा

20. वर्तमान समीक्षा से संबंधित कोई सूचना इस जाँच संबंधी अधिसूचना की तारीख से चालीस दिनों (दिनों 40) के भीतर उपर्युक्त पते पर प्राधिकारी के पास लिखित में भेजी जानी चाहिए। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है अथवा प्राप्त सूचना अधूरी होती है तो प्राधिकारी पाटनरोधी नियमावली के, अनुसार, "उपलब्ध तथ्योंके आधार पर अपने जाँच परिणाम दर्ज कर सकते हैं।"

21. सभी हितबद्ध पक्षकारों को एतद्वारा सलाह दी जाती है कि वे इस समीक्षा जाँच की शुरूआत की अधिसूचना की तारीख से दिनों के भीतर वर्तमान मामले में अपने हित 40 (हित के स्वरूप सहित) की सूचना दें और प्रश्नवली के अपने उत्तर दायर करें तथा घरेलू उद्योग के आवेदन पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें। यह सूचना मूल प्रति तथा साफ्ट प्रति दोनों में ही प्रस्तुत की जानी चाहिए।

गोपनीय आधार पर सूचना प्रस्तुत करना

22. प्रश्नवली के उत्तर सहित प्राधिकारी के समक्ष कोई अनुरोध (उससे संलग्न परिशिष्ट/अनुबंध सहित) प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों के लिए उसके किसी भाग के संबंध में" गोपनीयता "का दावा करने के मामले में निम्नानुसार दो अलग-अलग सैट प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा:-

(क). गोपनीय रूप से अंकित एक सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि); और

(ख). अगोपनीय रूप में अंकित दूसरा सैट (शीर्षक, सूची, पृष्ठ संख्या आदि)।

23. "गोपनीय "या" अगोपनीय "अनुरोधों पर स्पष्ट रूप से प्रत्येक पृष्ठ पर" गोपनीय "या" अगोपनीय "अंकित होना चाहिए। ऐसे अंकन के बिना प्रस्तुत सूचना को प्राधिकारी द्वारा अगोपनीय माना जाएगा और प्राधिकारी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ऐसी अगोपनीय सूचना का निरीक्षण करने की अनुमति देने के लिए स्वतंत्र होंगे। दोनों पाठों की हार्ड कॉपियों के साथ साफ्ट कॉपियां पॉच (5) सैट में प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है।

24. गोपनीय पाठ में ऐसी समस्त सूचना होगी जो स्वाभाविक रूप से गोपनीय है और/अथवा ऐसी अन्य सूचना जिसके ऐसी सूचना के प्रदाता द्वारा गोपनीय होने का दावा किया गया है। स्वाभाविक रूप से गोपनीय होने का दावा की गई सूचना या अन्य कारणों से गोपनीयता का दावा की गई सूचना के संबंध में सूचना प्रदाता को प्रदत्त सूचना के साथ ऐसे कारणों का विवरण प्रस्तुत करना होगा कि उस सूचना का प्रकटन क्यों नहीं किया जा सकता है।

25. अगोपनीय रूपांतरण को उस सूचना, जिसके बारे में गोपनीयता का दावा किया गया है, पर निर्भर रहते हुए अधिमानतः सूचीबद्ध या रिक्त छोड़ी गई (यदि सूचीबद्ध करना व्यवहार्य न हो) और सारांशीकृत गोपनीय सूचना के साथ गोपनीय रूपांतरण की अनुकृति होना अपेक्षित है। अगोपनीय सारांश पर्याप्त विस्तृत होना चाहिए ताकि गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की विषय वस्तु को समुचित ढंग से समझा जा सके। तथापि, आपवादिक परिस्थितियों में गोपनीय सूचना प्रदाता पक्षकार यह इंगित कर सकते हैं कि ऐसी सूचना का सारांश संभव नहीं है और प्राधिकारी की संतुष्टि के अनुसार इस आशय के कारणों का एक विवरण उपलब्ध कराया जाना चाहिए कि सारांश क्यों संभव नहीं है।

26. प्रस्तुत सूचना के स्वरूप की जांच करने के बाद प्राधिकारी गोपनीयता के अनुरोध को स्वीकार या अस्वीकार कर सकते हैं। यदि प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि गोपनीयता का अनुरोध अपेक्षित नहीं है अथवा सूचना प्रदाता उक्त सूचना को सार्वजनिक करने या सामान्य रूप में अथवा सारांश रूप में उसके प्रकटन को प्राधिकृत करने का अनिच्छुक है तो वह ऐसी सूचना की अनदेखी कर सकते हैं।

27. सार्थक अगोपनीय रूपांतरण के बिना या गोपनीयता के दावे के बारे में यथोचित कारण के विवरण के बिना किए गए किसी अनुरोध को प्राधिकारी द्वारा रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा।

28. प्रदत्त सूचना की गोपनीयता की जरूरत से संतुष्ट होने और उसे स्वीकार कर लेने के बाद प्राधिकारी ऐसी सूचना के प्रदाता पक्षकार के विशिष्ट प्राधिकार के बिना किसी पक्षकार को उसका प्रकटन नहीं करेंगे।

सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण

29. पाटनरोधी नियमावली के नियम 6 (7) के अनुसार कोई हितबद्ध पक्षकार उस सार्वजनिक फाइल का निरीक्षण कर सकता है जिसमें अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के अगोपनीय रूपांतरण रखे गए हैं।

असहयोग

30. यदि कोई हितबद्ध पक्षकार उचित अवधि के भीतर आवश्यक सूचना जुटाने से मना करता है अथवा उसे अन्यथा उपलब्ध नहीं कराता है या जांच में अत्यधिक बाधा डालता है तो प्राधिकारी अपने पास उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने जांच परिणाम दर्ज कर सकते हैं तथा केन्द्र सरकार को यथोचित सिफारिशें कर सकते हैं।

ए. के. भल्ला, अपर सचिव एवं निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Anti-Dumping and Allied Duties)

INITIATION NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd June, 2016

Subject: Initiation of anti-dumping investigation concerning imports of “Wire Rod of Alloy or Non-Alloy Steel” originating in or exported from China PR-reg.

No. 14/17/2016-DGAD.— M/s Steel Authority of India Limited, M/s Rashtriya Ispat Nigam Limited, M/s Usha Martin Limited and M/s JSW Steel Limited (hereinafter also referred to as petitioner companies or the applicants) have filed a petition before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the Authority) in accordance with the Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Act) and the Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Anti-Dumping Duty on Dumped Articles and for Determination of injury) Rules, 1995 as amended from time to time (hereinafter also referred to as the Rules) for initiation of anti-dumping investigation and imposition of anti-dumping duty on the alleged dumped imports of “Wire Rod of Alloy or Non-Alloy Steel”, originating in or exported from China PR (hereinafter also referred to as the subject country).

2. And whereas, the Authority prima facie finds that sufficient evidence of dumping of the subject goods, originating in or exported from the subject country, injury to the domestic industry and causal link between the alleged

dumping and the injury exist to justify initiation of an anti-dumping investigation, the Authority hereby initiates an investigation into the alleged dumping causing consequent injury to the domestic industry in terms of the Rules, to determine the existence, degree and effect of dumping and recommend the amount of anti dumping duty, which if levied, would be adequate to remove the injury to the domestic industry.

Product under Consideration

3. The product under consideration in the present investigation is bars and rods, hot-rolled, in irregularly wound coils, of iron or non-alloy steel or alloy steel (commonly known as "Wire Rods"). These products are of prime and non-prime category and are in all sizes. These products conform to various qualities of steels including but not limited to electrode, free cutting, forging, cold heading, low / medium / high carbon steels, drawing, ball bearing steel, case hardening steel, spring steel, corrosion resistant steel, weathering steel, structural steel and many more qualities of steel. The following products, however, are not included in the scope of the product under consideration:

a) Bars and rods containing indentations, ribs, grooves or other deformations produced during the rolling process falling under Tariff Item 72131090 (commonly known as rebars or TMT bars).

b) Bars and rods of Stainless steel falling under Tariff Heading 7221.

c) Bars and rods of High speed steel falling under Tariff Item 72271000

4. The PUC is used in many applications and sectors such as automotive components, welding electrodes, fasteners including nuts and bolts, nails, railway sleepers, general engineering, binding wires for construction industry, armoured cables etc.

5. The PUC is classified under Custom Tariff Heading 7213 and 7227. The Customs classification is, however, indicative only and is in no way binding on the scope of the present investigation.

Like Article

6. The applicants have claimed that the subject goods being produced by the domestic industry are similar to the subject goods being dumped into India. The applicants have claimed that PUC produced by the applicants and originating in or imported from the subject country are having comparable characteristics in terms of parameters such as physical & chemical characteristics, manufacturing process & technology, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The two are technically and commercially substitutable and hence should be treated as 'like article' under the Rules. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the applicants in India are being treated as 'like article' to the subject goods originating in or imported from the subject country.

Domestic Industry

7. The application has been filed by M/s Steel Authority of India Limited, M/s Rashtriya Ispat Nigam Limited, M/s Usha Martin Limited and M/s JSW Steel Limited. As per the information available on record, the production of the aforesaid producers accounts for a major proportion of the total domestic production in India. The Application has also been supported by two other domestic producers, namely, Tata Steel Limited and Jindal Steel and Power Limited.

8. The application, thus, satisfies the requirements of Rule 2(b) and Rule 5(3) of the Rules with regard to standing of the aforesaid domestic producers and that they are treated as domestic industry (DI) within the meaning of Rule 2(b) supra.

Countries involved

9. The country involved in the present investigation is China PR.

Normal Value

China PR

10. The applicants have submitted that China PR should be treated as a non-market economy country and have determined the normal value in accordance with Para 7 and 8 of Annexure I of the Rules. In terms of Para 8 of Annexure 1 to the Rules, it is presumed that the producers of the subject goods in China PR are operating under non-market economy conditions. In view of the non-market economy presumption and subject to rebuttal of the same by the responding exporters, the normal value of the subject goods in China PR has been estimated in terms of Para 7 of Annexure 1 to the Rules. The applicants have constructed the normal value for China PR based upon the cost of production in India, duly adjusted to include selling, general & administrative expenses and reasonable profit. The normal value claims of the applicants have been considered for the purpose of initiation.

Export Price

11. The applicants have determined the export price for the product under consideration for the subject country based on the transaction wise import data available from IBIS in India. Price adjustments have been made on account of Ocean Freight, Inland Freight, Ocean Insurance, Handling Charges and Non-Refundable VAT for the subject country.

Dumping Margin

12. The normal value and the export price have been compared at ex-factory level, which show significant dumping margins in respect of the subject country. There is sufficient *prima facie* evidence that the normal value of the subject goods in the subject country is significantly higher than the ex-factory export price, indicating, *prima facie*, that the subject goods are being dumped into the Indian market by the exporters from the subject country.

13. There is sufficient *prima facie* evidence of significant dumping margin to justify initiation of antidumping investigation.

Injury and Causal Link

14. The applicants have claimed that they have suffered material injury and have furnished evidence regarding the injury having taken place as a result of the alleged dumping from the subject country in terms of increase in imports in absolute terms and in relation to domestic production and domestic demand. The dumping from the subject country has resulted in deterioration of capacity utilisation, market share, inventories, profits, return on capital employed, cash profit etc. of the domestic industry.

15. The applicants have also claimed adverse price effects as evidenced by price suppression, price depression and price underselling. The Authority considers that there is sufficient *prima facie* evidence of injury being suffered by the applicants caused by the dumped imports of the subject goods originating in or exported from the subject country to justify initiation of an antidumping investigation.

Period of Investigation

16. The period of investigation (POI) for the present investigation is from July, 2015 to December, 2015. The injury investigation period will, however, cover the periods April 2012-March 2013, April 2013-March 2014, April 2014-March 2015, April 2015-Dec 2015 (Annualized) and the POI.

Retrospective imposition of duties

17. The applicants have requested for retrospective imposition of the antidumping duty due to following reasons:
a. There is history of dumping and that the importers should have been aware that exporters practice dumping and that such dumping caused injury to the domestic industry.

b. The injury to the domestic industry has been caused by massive dumping of the subject goods in a relatively short time which in the light of the timing and volume of imported subject goods dumped and other circumstances is likely to seriously undermine the remedial effect of the antidumping duty liable to be levied.

18. The interested parties may make their submissions in this regard.

Submission of information

19. The known exporters in the subject country and their Government through their Embassy in India, importers and users in India known to be concerned with the subject goods and the domestic industry are being informed separately to enable them to file all the relevant information in the form and manner prescribed within the time limit set out below. Any other interested party may also make its submissions relevant to the investigation in the form and manner prescribed within the time limit set out below. The information/submissions may be submitted to:

The Designated Authority,
Directorate General of Anti-Dumping & Allied Duties,
Ministry of Commerce & Industry,
Department of Commerce
Government of India
4th Floor, Jeevan Tara Building, 5, Parliament Street,
New Delhi-110001

Time Limit

20. Any information relating to the present investigation should be sent in writing so as to reach the Authority at the address mentioned above not later than forty days (40 days) from the date of this Initiation Notification. If no information is received within the prescribed time limit or the information received is incomplete, the Authority may record its findings on the basis of the facts available on record in accordance with the AD Rules.

21. All interested parties are hereby advised to intimate their interest (including the nature of interest) in the instant matter and file their questionnaire responses and offer their comments to the domestic industry's application within forty days (40 days) from the date of issuance of the letter intimating initiation of the investigation. The information must be submitted in hard copies as well as in soft copies.

Submission of information on confidential basis

22. The parties making any submission (including Appendices/Annexure attached thereto), before the Authority including questionnaire response, are required to file the same in two separate sets, in case "confidentiality" is claimed on any part thereof:-

- a) one set marked as Confidential (with title, number of pages, index, etc.), and
- b) the other set marked as Non-Confidential (with title, number of pages, index, etc.).

23. The "confidential" or "non-confidential" submissions must be clearly marked as "confidential" or "non-confidential" at the top of each page. Any submission made without such marking shall be treated as non-confidential by the Authority and the Authority shall be at liberty to allow the other interested parties to inspect such submissions. Soft copies of both the versions will also be required to be submitted, along with the hard copies, in five (05) sets of each.

24. The confidential version shall contain all information which is by nature confidential and/or other information which the supplier of such information claims as confidential. For information which are claimed to be confidential by nature or the information on which confidentiality is claimed because of other reasons, the supplier of the information is required to provide a good cause statement along with the supplied information as to why such information cannot be disclosed.

25. The non-confidential version is required to be a replica of the confidential version with the confidential information preferably indexed or blanked out (in case indexation is not feasible) and summarized depending upon the information on which confidentiality is claimed. The non-confidential summary must be in sufficient detail to permit a reasonable understanding of the substance of the information furnished on confidential basis. However, in exceptional circumstances, a party submitting the confidential information may indicate that such information is not susceptible to summary, and a statement of reasons why summarization is not possible must be provided to the satisfaction of the Authority.

26. The Authority may accept or reject the request for confidentiality on examination of the nature of the information submitted. If the Authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or if the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorize its disclosure in generalized or summary form, it may disregard such information.

27. Any submission made without a meaningful non-confidential version thereof or without good cause statement on the confidentiality claim shall not be taken on record by the Authority.

28. The Authority on being satisfied and accepting the need for confidentiality of the information provided, shall not disclose it to any party without specific authorization of the party providing such information.

Inspection of Public File

29. In terms of Rule 6(7) of the Rules, any interested party may inspect the public file containing non-confidential version of the evidence submitted by other interested parties.

Non-cooperation

30. In case where an interested party refuses access to, or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period, or significantly impedes the investigation, the Authority may record its findings on the basis of the facts available to it and make such recommendations to the Central Government as deemed fit.

A. K. BHALLA, Addl. Secy. and Designated Authority